पोस्टल रजिस्ट्रेशन नं. HP/DMA/113

Changing Ways
बदलती राहें
(साप्ताहिक)

❑ वर्ष 01 ❑ अंक 11 ❑ पृष्ठ : 04 ❑ मूल्य : 4 रुपये | धर्मशाला, 23 मई 2016 | हर सोमवार को प्रकाशित

संस्कृतियों के समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण है फ्यूज़न

धर्मशाला : कांगड़ा जिला प्रशासन की पहल पर पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पिछले सप्ताह से आरंभ कार्यक्रम फ्यूज़न भारत तथा तिब्बत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को जानने एवं समझने का बेहतर अवसर सिद्ध हो सकता है।

इस योजना के अन्य उद्देश्यों में देशी तथा विदेशी पर्यटकों के अतिरिक्त स्थानीय युवाओं को दोनों देशों की बेजोड़ संस्कृतियों के बारे में अवगत करवाना, उनमें रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहन देना और उन्हें नशे से दूर रखना आदि शामिल हैं। पर्यटकों एवं स्थानीय लोगों को इस योजना के तहत सैन्य संस्कृति से भी रू-ब-रू करवाया जा रहा है। गत शनिवार को मैक्लोडगंज में आयोजित फ्यूज़न के अन्तर्गत पर्यटकों तथा स्थानीय लोगों को हिमाचल प्रदेश, तिब्बत तथा भारतीय सेना को संस्कृतियों को जानने का अवसर मिला। इस कड़ी में आयोजित पहले कार्यक्रम में राज्य सरकार के सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, टिपा (तिब्बत कला निष्पादन संस्थान) तथा भारतीय सेना के कलाकारों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से न केवल स्थानीय लोगों बल्कि देशी तथा विदेशी कलाकारों का मन मोह लिया। शहनाई वादन से आरम्भ कार्यक्रम में लोक सम्पर्क विभाग के कलाकारों ने पहाड़ी लोक गीतों पर आधारित धुनें, लोक गीत तथा झमाकड़ा, टिपा के कलाकारों ने सिंह नृत्य तथा मेलारपा और भारतीय सेना के जवानों ने भांगड़ा तथा पंजाबी युद्ध कला पर आधारित गतका प्रस्तुत किया। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग के सौजन्य से आयोजित इन कार्यक्रमों में राज्य लोक सम्पर्क विभाग तथा टिपा स्थाई सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। उपायुक्त रितेश चौहान बताते हैं कि ये कार्यक्रम हर सप्ताह विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे। इनमें व्यावसायिक कलाकारों के अलावा शौकिया किन्तु दक्ष कलाकारों को भी अपनी प्रतिभा दर्शाने का अवसर मिलेगा। विभिन्न संस्थानों के कलाकारों एवं छात्रों को अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए इससे बेहतर मंच शायद ही मिले।

धर्मशाला एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में भूस्खलन की गंभीर स्थिति

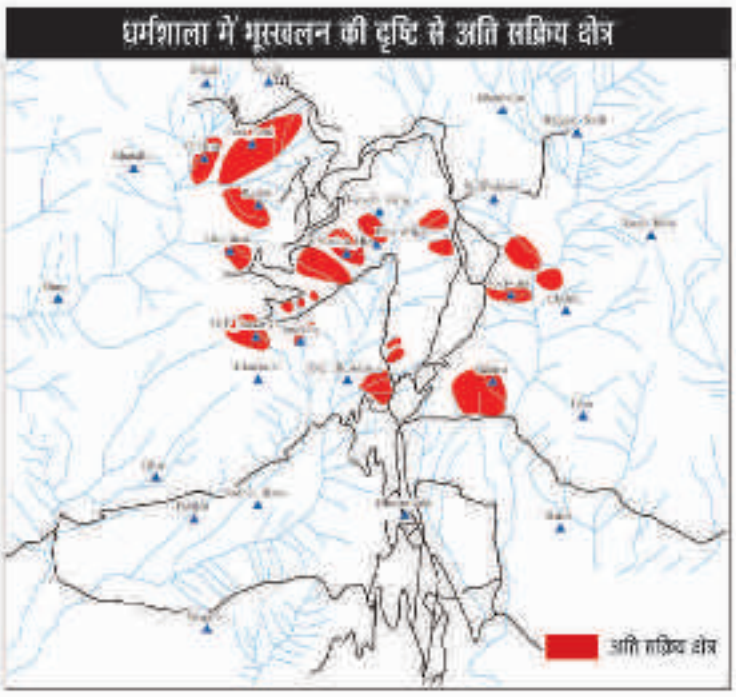

धर्मशाला में भूस्खलन की दृष्टि से अति सक्रिय क्षेत्र

पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन एवं भूखंडों का खिसकना एक आम बात है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं। टेक्टोनिकली हिमालय क्षेत्र इस संबंध में अति संवेदनशील माना गया है। यहां भूगर्भ में होने वाली प्रतिक्रिया का प्रभाव सतह पर होना टाला नहीं जा सकता, लेकिन धर्मशाला एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में भूस्खलन तथा भूमि कटाव के कारण जो परिदृश्य उभर रहा है उसके कारण कुछ और हैं। अनियोजित विकास, निर्माण कार्यों में लापरवाही और अंधाधुंध पेड़ों का काटा जाना सबसे बड़ा कारण है। डॉ. अंबरीश महाजन जिन्होंने धर्मशाला क्षेत्र की भूगर्भीय संरचना के बारे में अनेकों बार विस्तृत अध्ययन एवं शोध कार्यों का संचालन एवं प्रतिपादन किया है, इस संबंध में गंभीर और चिंतित हैं। एकमात्र वरिष्ठ भूगर्भ विज्ञानी जो धर्मशाला में ही जन्मे, पढ़े-लिखे और यहां की मिट्टी की खुशबू से बखूबी परिचित डॉ. महाजन इस शहर की दुर्गति पर आशंकित हैं। उनके अनुसार बढ़ती विकासात्मक गतिविधियां, द्रुत शहरीकरण और दिनोंदिन फैलते सड़कों के जाल ने शहर की सुंदर ढलानों को बुरी तरह से झिंझोड़ कर रख दिया है तथा इन्हें रिहाइश, कृषि तथा बागवानी के लिए असुरक्षित बना दिया है। धर्मशाला शहर तथा आसपास के क्षेत्र कांगड़ा घाटी में अनियोजित शहरी विकास के ज्वलंत उदाहरण बन कर उभर रहे हैं। यदि वर्तमान परिस्थिति का गंभीर अध्ययन करें तो निकट भविष्य में भारी भूस्खलन तथा भूकंप जैसी आपदाओं की बढ़ती संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता बल्कि आशंकाएं बढ़ती नज़र आती हैं। शहर के कई महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में पिछले कुछ समय में ऐसी कई घटनाएं घटित हुई जिन्हें प्रशासन ने लीपापोती करके छुपा तो दिया था लेकिन विकास क्रम और निर्माण कार्यों में कोई सैद्धांतिक परिवर्तन नहीं आया। सरकार की ओर से कोई गंभीर प्रयास किए गए हों ऐसा भी नहीं दिखता। नगर एवं ग्राम योजना विभाग हो या नगर निगम इस दिशा में कोई भी गंभीर नहीं। कच्ची ढलानों पर भारी इमारतें अब भी वैसे ही बेरोकटोक बन रही हैं। बरसात के मौसम में पानी का ज़मीन के अंदर समा जाना मिट्टी की नमी बढ़ा देता है और भूमि की धारण क्षमता कम हो जाती है। इसके कारण भूस्खलन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और भूकंप की स्थिति में होने वाला नुकसान कई गुणा बढ़ जाता है। इसलिए जल निकासी का प्रबंध बहुत ही गंभीरता से किया जाना आवश्यक है। इसके लिए नियमों में कड़े प्रावधान होने ज़रूरी हैं। कच्चे सैप्टिक टैंक तथा सोक पिट्स का भी भूस्खलन में बड़ा योगदान रहता है। जब सीवरेज व्यवस्था लागू हो जाए तो भी इनका अच्छी तरह से भरा जाना अत्यावश्यक है ताकि पानी का रिसाव पूरी तरह से रोका जा सके। इमारतों और सड़कों के साथ बनी हुई नालियों का निरीक्षण करके उनसे होने वाले रिसाव को रोकने के भरपूर प्रयास किए जाने चाहिए। बरसातों से पहले भूमि के कटाव से होने वाले जल रिसाव का रोका जाना सबसे बड़ी चुनौती है।

पर्यटकों के लिए खुला रोहतांग

कुल्लू। सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल रोहतांग दर्रा पर्यटन गतिविधियों के लिए खोल दिया गया है। जिला प्रशासन और एनजीटी के सदस्यों के साथ संयुक्त निरीक्षण के बाद पर्यटकों को रोहतांग दर्रे तक जाने की इजाजत देने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त हंसराज चौहान ने बताया कि एनजीटी आदेशों का पालन करते हुए जिला प्रशासन ने रोहतांग में पर्यटकों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवा रखी हैं। उन्होंने सभी पर्यटकों तथा पर्यटन व्यवसाय से जुड़े तमाम व्यावसायियों से अपील की है कि वे रोहतांग में सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने बताया कि रोहतांग व इसके आसपास के पर्यटक स्थलों पर केवल परमिट धारकों को ही पर्यटन से संबंधित गतिविधियां व कारोबार करने की अनुमति दी गई है। यदि किसी के पास परमिट नहीं होगा तो उसे किसी भी प्रकार का कारोबार करने की अनुमति नहीं होगी।

सर्टिफिकेट कोर्स हेतु नामांकन आवेदन पत्र

सर्टिफिकेट कोर्स हेतु 'गुंजन' संस्था द्वारा संचालित क्षेत्रीय संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र, नर्बदा-II, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार एवं डिफेंस स्कूटर्स अर्थात लिमिटेड के सहयोग से आगामी तीन माह (8 मई प्रारंभिक) के ट्रेनिंग कार्यक्रम हेतु नामांकन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

Course Title	Duration	Eligibility	No of Seats	Course Fee
Certificate Course in Radio Jockey & Anchoring	3 Months	10+2 or Equivalent	25	Rs 6000/-
Certificate Course in Front Office Executive	3 Months	10+2 or Equivalent	25	Rs 4500/-
Certificate Course in Website Designing	3 Months	10+2 or Equivalent	25	Rs 7500/-
Certificate Course in Graphic Designing	3 Months	10+2 or Equivalent	25	Rs 7500/-
Certificate Course in Entrepreneurship Development	3 Months	10+2 or Equivalent	25	Rs 9000/-
Certificate Course in Restaurant Service Staff	3 Months	10th or Equivalent	25	Rs 4500/-

चयन 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर होगा। नामांकन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून, 2016 है। पाठ्यक्रम तथा प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित कोई भी जानकारी हमारे ऑफिस से कार्यालय समय के दौरान प्राप्त की जा सकती है।

❑ नशे से पीड़ित व्यक्ति व उनके परिवार-जनों, एचआईवी संक्रमित व्यक्ति व उनके परिवार-जनों, जोखिम पूर्ण व्यवहार के व्यक्तियों तथा पीड़ित व्यक्तियों के आश्रित एवं विकलांग व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी एवं फीस में भी रियायत दी जाएगी।

संपर्क व्यक्ति अजय कुमार (01892-235313, 9459302504)

आवेदन पत्र/नामांकन कार्यकारी निदेशक, गुंजन ऑर्गेनाईजेशन सामुदायिक विकास, सर्वोदय रोड, सिद्धबाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश-176057, फोन नं. 01892-235313, 9459302504 के पास भेजे जा सकते हैं।

Changing Ways
बदलती राहें
धर्मशाला, 23 मई 2016

नतीजों में फिसड्डी साबित हो रहे सरकारी गुरुजी

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की दसवीं की परीक्षा के नतीजे घोषित होने के साथ ही सरकारी स्कूलों के खराब नतीजों पर एक बार फिर बहस शुरू हो चुकी है। इस बार 102 सरकारी स्कूलों दसवीं की परीक्षा का परिणाम 20 फीसद से कम रहा है। वहीं 21 से 50 फीसदी परिणाम देने वाले स्कूलों की संख्या 887 बताई गई है। सौ फीसदी परिणाम सिर्फ 175 सरकारी स्कूल ही दे पाए हैं। मैरिट में सिर्फ दो ही बच्चे आ पाए हैं। अब सरकारी स्कूलों के अध्यापकों और सुविधाओं की बात करें तो सरकारी स्कूलों में जहां हर प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। वहीं निजी स्कूलों की तुलना में सरकारी अध्यापकों की शैक्षणिक क्षमता कहीं अधिक होती है। जहां निजी स्कूलों में सिफारिश या कम वेतन के आधार पर शिक्षकों की तैनाती होती है, तो वहीं सरकारी स्कूलों में प्रवेश स्तरीय भर्ती परीक्षा से गुजरना पड़ता है।

सरकारी स्कूलों के अध्यापकों का वेतन निजी स्कूलों की तुलना में कहीं अधिक संतोषजनक होता है। अगर अनुबंध अध्यापकों को छोड़ दें तो एक नियमित सरकारी अध्यापक जितना वेतन ले रहा है, उसकी तुलना में निजी स्कूल का अध्यापक कहीं नहीं टिकता। इसके बावजूद अगर निजी स्कूलों के कम वेतन व असुरक्षित नौकरी करने वाले अध्यापक अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं और सरकारी नौकरी पाने वाले फिसड्डी साबित हो रहे हैं, तो यह स्थिति सरकार के लिए चिंता का सबब जरूर है। हालांकि अक्सर सरकारी अध्यापकों की यही शिकायत रहती है कि उन्हें पढ़ाने के अलावा अन्य कई काम दिए जाते हैं और कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, मगर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकारी नौकरी करने वाले अन्य कर्मियों की तरह ही अध्यापक भी कहीं न कहीं कार्य संस्कृति व अपनी जिम्मेवारी से विमुख होते जा रहे हैं। बच्चों के भविष्य से ज्यादा उन्हें तबादलों, राजनीति और अपनी सुख सुविधाओं की चिंता रहती है। खासकर सरकारी नौकरी पाने के बाद जो मानसिकता बनती जा रही है, उसे भी बोर्ड की परीक्षा के परिणाम से जोड़ा जा सकता है। वैसे इस स्थिति के लिए सरकार भी कम जिम्मेवार नहीं है। अध्यापकों को स्थानांतरण से लेकर गैर शैक्षणिक ड्यूटी में उलझाए रखना भी उनकी दक्षता को कुछ हद तक बाधित करता है।

सरकारी स्कूलों में अधिकतर ग्रामीण परिवेश और गरीब वर्ग के बच्चे ही अधिक जाते हैं। ऐसे में अगर उनके भविष्य को संवारने वाले गुरु जी इस तरह का परिणाम देंगे तो प्रदेश और देश का भविष्य खतरे में माना जा सकता है। इसके लिए सरकार को जहां एक दमदार नीति बनानी होगी, वहीं अध्यापकों पर से अनावश्यक बोझ को भी कम करना होगा, तभी उनसे अच्छे परिणाम की उम्मीद की जा सकती है।

महाविनाश तैयार है, अभी वक्त है संभल जाईए

वैज्ञानिकों का अनुमान है कि समय रहते हमारे न चेतने से हम अगली आधी सदी या शायद इससे भी कम समय में पृथ्वी से उसी तरह गायब हो सकते हैं, जैसे नदी में जल न होने पर विद्युत उत्पादन। धरती के गर्माने से जैव विविधता नष्ट हो रही है और आए दिन प्राकृतिक आपदाओं में हो रही वृद्धि हमारे विनाश का द्योतक है।

भारत रत्न से अलंकृत तथा दादा साहिब फाल्के पुरस्कार विजेता कवि प्रदीप ने नास्तिक फिल्म (1954) के लिए 'देख तेरे संसार की हालत, क्या हो गई भगवान' गीत लिखते समय कभी नहीं सोचा होगा कि जिस गीत की रचना वह मानवीय स्वभाव तथा सम्बन्धों को लेकर कर रहे हैं, वह यथार्थ पर इतना सटीक उतरेगा। पिछले कुछ अर्से से कुछ टीवी चैनलों तथा समाचार-पत्रों में वर्तमान में पृथ्वी की दुर्दशा एवं भविष्य में इसके नामो-निशान के मिटने की सम्भावनाओं को लेकर की गई रिपोर्टों को देख-पढ़ कर किसी भी व्यक्ति का चिंतातुर होना लाजिमी है। विश्व समुदाय के एक बड़े वर्ग में पनपने और आए दिन होने वाले नए अनुसंधानों से हो सकता है कि अगले कुछ सालों में चांद पर उसी तरह जीवन सम्भव हो जाए, जिस प्रकार गंजे के सिर पर बालों के लिए आजकल साईंसदान बाल प्रत्यारोपण तकनीक का सहारा ले रहे हैं। चांद पर मौजूद खनिजों के दोहन के बाद, अन्य ग्रहों पर यात्राएं आरम्भ करने के लिए उसे स्टेशन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। पर गरीबों के लिए चांद भविष्य में भी दूर की ही कौड़ी रहेगा। उन्हें इसी धरती पर जीवन बसर करना होगा और अगर हम इसी तरह और रफ्तार से पृथ्वी का शोषण करते रहे और प्रदूषण फैलाते रहे, तो आने वाले समय में जमीन पर हमारा सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा, हो सकता है कि अगले 100 सालों में हमें महाविनाश भी झेलना पड़े। कम से कम वैज्ञानिक अध्ययन में तो यही बात उभरकर सामने आ रही है।

भले ही पिछले कुछ सालों से जलवायु में परिवर्तन के साथ-साथ आतंकवाद, परमाणु प्रसार, ईराक सहित कुछ देशों में सत्ता परिवर्तन, आर्थिक मंदी जैसे विषय अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते रहे हों, पर मौसम में बदलाव का मुद्दा सबसे अधिक चिन्ता का विषय रहा है। मौसम में बदलाव के कारण भी किसी से छिपे नहीं हैं। महात्मा गांधी के मंत्र को याद रखकर अगर हम प्रकृति के साथ दोस्ताना कायम रख सके होते तो आज हमें पर्यावरण पर प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की आवश्यकता शायद ही पड़ती। हमारे लालच ने आज हमें उस मुकाम पर ला खड़ा किया है, जहां हमारे अस्तित्व पर प्रश्नचिन्ह लगना आरम्भ हो गए हैं। ऐसे में हमारा चांद की ओर रुख करना स्वाभाविक है। पर यह समस्या का समाधान नहीं है। हो सकता है कि चांद पर बसने के बाद इसे मानवीय सभ्यता की सबसे बड़ी उपलब्धि कहा जाए, पर धरती को इस तरह नजरअंदाज किया जाना हमारे विनाश का कारण होगा। जलवायु में हो रहे परिवर्तनों का पिछले कुछ सालों में हम खामियाजा भर चुके हैं। ईसा की दूसरी शताब्दी में पूरे विश्व की जनसंख्या महज पांच करोड़ थी, जो आज छः अरब से भी अधिक हो गई है। सभ्यता के विकास के साथ प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बढ़ना स्वाभाविक था। परन्तु हमारे अनियोजित औद्योगिक विकास ने पर्यावरण को जो ठेस पहुंचाई है, उसे पूरा करने के लिए हमें सैंकड़ों वर्ष लगेंगे।

वैज्ञानिकों का अनुमान है कि समय रहते हमारे न चेतने से हम अगली आधी सदी या शायद इससे भी कम समय में पृथ्वी से उसी तरह गायब हो सकते हैं, जैसे नदी में जल न होने पर विद्युत उत्पादन। धरती के गर्माने से जैव विविधता नष्ट हो रही है और आए दिन प्राकृतिक आपदाओं में हो रही वृद्धि हमारे विनाश का द्योतक है। सार्वजनीन हित का मुद्दा होने के बावजूद यह अभी भी सार्वभौमिक नहीं बन पाया है। सभी देशों के हित आड़े आते हैं, जो टकराव के बुनियादी कारण हैं। जंगल आए दिन कम हो रहे हैं और अन्धाधुंध उद्योगों की स्थापना से वायुमंडल में कार्बन डाई-ऑक्साईड की मात्रा बढ़ रही है। जब तक कोई सर्वसुलभ स्रोत सामने नहीं आता है, तब तक जीवाश्मजनित ईंधन का प्रयोग रुकना नामुमकिन है। क्योटो में सम्पन्न मौसम परिवर्तनपरक मसविदे के बाद अब कोपेनहेगन में होने वाले परामर्श का भी भविष्य भी इससे अलग नहीं है। अमेरिका एवं उसके पिछलग्गुओं द्वारा चीन और भारत को ही कार्बन डाई-ऑक्साईड उत्सर्जन के लिए जिम्मेवार ठहराने और भारत तथा चीन द्वारा संकट के लिए अमेरिका एवं यूरोप के पूंजीवादी देशों को इसके लिए उत्तरदाई कहने से इस समस्या का हल निकलने वाला नहीं। सार्वभौमिक हितों को ध्यान में रखकर सभी देशों को कार्बन मुक्ति का कोई ऐसा फार्मूला ढूंढना होगा, जो सभी को मान्य हो। अगर अपने देश की बात करें तो भारत में इस साल सूखे से शायद ही कोई राज्य अप्रभावित रह पाया हो। बेतहाशा शहरीकरण और औद्योगिकीकरण से गांवों में बसने वाले भारत का स्वरूप बदलता जा रहा है। छोटी से छोटी मदद के लिए भी लोग सरकार की ओर टकटकी लगाकर देखते हैं और उनका यही रवैया घातक सिद्ध हो रहा है। वनीकरण, जल संचयन, जल प्रबंधन जैसी बातों को लोग पहले स्थानीय स्तर पर खुद संचालित करते थे। अब जब सरकार ऐसी योजनाओं को लेकर लोगों के घर-द्वार पर आ रही है, तो लोग इसमें सहयोग करने तथा इनका लाभ उठाने की बजाए इसे सरकारी मानकर मुंह फेर लेते हैं। हमारे शास्त्रों में वन और जल के महत्व और संरक्षण पर बहुत कुछ लिखा गया है। पर आधुनिक सुख-सुविधाओं के जाल में उलझ चुका हमारा जनमानस खुद कुछ करने को तैयार नहीं। 1929 में जन्में श्रीपद अच्युत दाभोलकर द्वारा कृषि वृत्ति तकनीक से महाराष्ट्र, गुजरात तथा मध्य प्रदेश में प्रयोग परिवार संस्था ने जो कर दिखाया है, उसे आज पूरे देश में लागू करने की आवश्यकता है। इस तकनीक से स्थानीय परिवेश को ध्यान में रखकर भूमि से मनमानी उपज ली जा सकती है। दो कनाल भूमि में पांच आदमियों का परिवार आसानी से साल भर के भोजन का प्रबन्ध कर सकता है, पर मेहनत का कोई विकल्प नहीं। लोगों को सहभागिता करनी ही होगी। हमारे राज्य का परिदृश्य भी इससे अलग नहीं। सरकारी योजनाएं लोगों का इन्तजार कर रही हैं। पर हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने को तैयार नहीं। बन्दरों की समस्या हमारी बढ़ाई हुई है। अगर हम जंगल नहीं उजाड़ते और बन्दरों को नहीं पालते तो हमारे खेत सुरक्षित रहते।

मीडिया में आजकल जलवायु परिवर्तन का मुद्दा छाया है, कल कोई और होगा, उसके बाद शायद कोई और। इसी तरह विषय बदलते रहेंगे। पर स्थिर विकास अभी भी प्रासंगिक है और आने वाले समय में उतना ही महत्वपूर्ण रहेगा। उजड़ते खेतों, वनों, प्रदूषण और अनियोजित विकास की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए मीडिया को कमर कसनी होगी। ऋषि-आधुनिक तकनीक सम्मिश्रित खेती, वर्षा जल संचय-प्रबन्धन, वनीकरण और अन्य योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक बनाना होगा, ऐसा न करने पर होने वाली हानियों के बारे में बताना होगा। खाली खेतों में किया जा रहा बेतरतीब भवन निर्माण अन्न पैदा नहीं कर सकता। हमें खेत फिर बीजने ही होंगे। फिलहाल वर्तमान समाज नागरिक अपनी चेतना बनाए रखिए और बच्चे का यह शेर पढ़िए,

'चांद से लाएंगे हम गेहूं की बोरियां,
जमीं पर बसे जाते हैं, सैंकड़ नए नगर।

–अजय पाराशर

अस्तित्व का साक्षी है ईश्वर

चिंतन

ईश्वर न पुरस्कृत करता है न दंडित करता है। वह तो केवल साक्षी है हमारे अस्तित्व का, आधार है हमारे जीवन का और प्रतिनिधि है उस विस्तार का जिसका हम अंश हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि सुख प्राप्त हो। कि ईश्वर हमें सुख दे। हम अमर हो जाएं। इत्यादि। यह प्रार्थना कौन करता है और किसके सम्मुख करता है और इस प्रार्थना को ग्रहण कौन करता है। यह और इसी प्रकार के अनेक प्रश्न हैं जिनका उत्तर खोजते-खोजते कितने ही लोग समा गए समय के गर्त में। जो कहा और जो अभिव्यक्त किया अधूरा ही रहा। आज भी ये सारे प्रश्न यथावत खड़े हैं। कोई न कोई जिज्ञासु इन्हें दोहराने लग ही जाता है। विराट का विद्रूप एक क्षण में मानवीय व्यवस्था को तहस-नहस करके रख देता है और अपने वर्चस्व का प्रमाण प्रस्तुत कर देता है, परंतु उसने कभी किसी मनुष्य से प्रश्न नहीं पूछा और न कभी किसी को अपने अस्तित्व और सामर्थ्य के लिए चेताया। मनुष्य का संसार भौतिक संसार से अलग भी है और उस पर आधारित भी है। सृजन, स्थिति और संहार चिर-परिचित परिस्थितियां हैं जिन्हें मानव ने अनेक रूपों और दिशाओं से अपने अनुकूल करने का प्रयास किया और आज भी जारी है, लेकिन कभी ऐसा हो नहीं पाया। होगा भी नहीं। जब तक मेरा अहं, मेरा निजी अहं रहेगा अमरत्व की भावना ही निराधार है। अहं का अमर होना सम्भव है ही नहीं, जब तक उसमें समय की सत्ता का प्रभाव है। अहं जब ईश्वरीय हो जाए तो वह अमर है ही। अहं को उत्सर्जित करके ईश्वरीय सत्ता में विलीन कर देना ही समाधान है। प्रार्थना का इससे अलग कोई रूप सिद्ध नहीं हो सकता।

संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है। असंभव से भी आगे निकल जाना।
–स्वामी विवेकानंद

पाठकों के लिए

विभिन्न सामाजिक, साहित्यिक एवं धार्मिक विषयों पर सभी प्रबुद्ध पाठकों के लेख, लघु कथाएं तथा कविताएं आमंत्रित हैं।

हमारा पता

संपादक,
बदलती राहें, एजन भवन, तपोवन रोड चोपोखा सिद्धबाड़ी, धर्मशाला
जिला कांगड़ा (हि.प्र.) -176057
Mail : badaltiraahein@gmail.com

पत्रकारिता बनाम पीतकारिता

-अजय पाराशर

मुखांक से आगे...
टूई की मस्तूतियों में छोटे बाजार में सक्रिय मीडिया उद्यमियों पर तो रोक लगाई जा सकती है, किन्तु जो बड़े समूह हैं और जो एक साथ हिन्दी और अंग्रेजी सहित दो-तीन भाषाओं के बाजार में सक्रिय हैं, उनको कोई खास मुश्किल पेश नहीं आएगी क्योंकि उनके लिए हर बाजार में अलग-अलग हिस्सा तय है। मीडिया में जिस तरह प्रकार के गुप्तयुग तरीके से निवेश का चलन बढ़ा है, उससे कई बार असली मालिक का पता करना मुश्किल होता है। उदाहरण के रूप में रिलायंस के मीडिया समूह इंडिपेंडेंट मीडिया ट्रस्ट को सामने रखा जा सकता है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने करीब दो साल पहले कहा था कि मीडिया उद्योग में कंट्रोल या नियंत्रण को स्वामित्व की तरह देखा जाना चाहिए। इसी तरह वर्ष 2008 में पेड न्यूज सम्बन्धी भारतीय प्रेस परिषद् की रिपोर्ट के बाद संसद की स्थाई समिति ने पिछले वर्ष इसी के सन्दर्भ में विस्तृत रिपोर्ट सौंपी थी।

समिति के अनुसार मीडिया लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्याप्त धारणाओं के अनुसार मीडिया न केवल लोगों की समस्याओं को आवाज देता है, बल्कि देश की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य की सही तस्वीर प्रस्तुत करता है। अतः आवश्यक हो जाता है कि विभिन्न संचार माध्यमों- समाचार-पत्र, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, मोबाइल फोन पर प्रकाशित और प्रसारित किए जाने वाली खबरें और कार्यक्रम ज्ञानवर्धक, तथ्यात्मक, निष्पक्ष, तटस्थ और विश्वसनीय हों। किन्तु मीडिया के कुछ हिस्सों में व्यक्तियों, संगठनों या निगमों आदि के पक्ष में सामग्री प्रकाशित और प्रसारित करने के बदले धनराशि या अन्य प्रकार के लाभ लिए जाने आरम्भ हो गए हैं, जिसे पेड न्यूज कहा जाता है। इस प्रवृत्ति का दुष्प्रभाव निर्णय, प्रतिभूति, जमीन-जायदाद व्यवसाय, स्वास्थ्य क्षेत्र एवं अन्य उद्योगों पर पड़ रहा है। निर्वाचन प्रक्रिया में जनमत भी प्रभावित हो रहा है। 'पेड न्यूज' का मसला कुछ पत्रकारों के भ्रष्टाचार तक ही सीमित नहीं है, इसमें मीडिया कम्पनियों के मालिक, प्रबन्ध निदेशक, जन सम्पर्क कम्पनियां, विज्ञापन एजेंसियां और कई राजनेता भी शामिल हैं। इस तरह मीडिया का इस हद तक समझौतावादी हो जाना चिन्ताजनक है। इस रिपोर्ट में पेड न्यूज के सन्दर्भ में मीडिया की मौजूदा स्थिति को लेकर चिन्ता जाहिर की गई है। किन्तु हैरानी की बात है स्थायी समिति ने जनप्रतिनिधियों के विज्ञापनदाता के रूप में विकास और उसकी पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश नहीं की है।

संसदीय समिति का सांसदों और विधायकों की बदलती भूमिका तथा पेड न्यूज के नए रूप के साथ रिश्ते बनाने की प्रक्रिया पर ध्यान ही नहीं गया है। इस तथ्य को बुनियादी तौर पर स्वीकार किया जाना चाहिए कि भूमंडलीकरण की आर्थिक नीतियों ने लोकतंत्र की तमाम संस्थाओं को बेपर्दा किया है। किन्तु सभी संस्थाएं लोकलाज के चलते बेशर्मी के साथ अपनी बला दूसरे के सिर डाल देती हैं। भारतीय प्रेस परिषद् की उप-समिति की रिपोर्ट कहती है कि प्रदत्त समाचार 'समाचार' के वेश में भ्रष्टाचार का संस्थागत और संगठित रूप है। प्रेस आयोग की रिपोर्ट बताती है कि किस प्रकार सरकारें भी अन्य विज्ञापनदाताओं की तरह विज्ञापनों के माध्यम से मीडिया पर दबाव बनाती हैं। इसे वर्ष 2008 के दिल्ली विधान सभा चुनाव के सन्दर्भ में मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और वर्तमान में मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के उदाहरणों से समझा जा सकता है। शीला दीक्षित के अनुसार अपनी उपलब्धियों को विज्ञापित करना हर सरकार का हक है, जबकि केजरीवाल तो बिना उपलब्धियों के ही भारी-भरकम बजट के साथ अपनी इनिंग खेल रहे हैं। विज्ञापन के रूप में सरकार के हक और चुनाव के दौरान मालदार प्रत्याशियों के खर्च के रूप में विज्ञापन के जरिए प्रचार को लेकर नई बहस खड़ी हो जाती है।

गत लोकसभा चुनावों के दौरान भी पेड न्यूज का नया चेहरा सामने आया था। अब इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढना अनिवार्य हो गया है कि चुनावों में विज्ञापनों की भूमिका क्यों बढ़ी है? क्यों कोई मीडिया कम्पनी किसी राजनेता के पक्ष में मतदाताओं को भ्रमित करने का प्रयास करती है और राजनेताओं में मतदाताओं को ठगने की प्रवृत्ति किस प्रकार विकसित हुई है तथा दिन पर दिन कैसे बढ़ रही है? वास्तव में तमाम राजनीतिक पार्टियां और उनके उम्मीदवार विज्ञापनदाता भी हैं और विज्ञापन की आवश्यकता भूमंडलीकरण की आर्थिक नीतियों और उससे उपजे वातावरण की देन है। प्रदत्त समाचार राजनीतिक प्रश्न में तब्दील हो चुका है। वर्ष 1991 के बाद सभी जन प्रतिनिधियों में होड़ लग गई है कि वे अधिक से अधिक अपना व्यक्तिगत प्रचार करें और सार्वजनिक कल्याणकारी कामों में अव्वल दिखें। विभिन्न समाचार चैनलों में अपने लिए और अपनी पार्टी के लिए लाखों- झपटते जन प्रतिनिधियों के दृश्य प्रायः देखे जा सकते हैं।

विज्ञापन की प्रथा बढ़ते पूंजीवाद की सैद्धांतिक देन है। इसे औद्योगिक उत्पादों के विक्रय के प्रचार-प्रसार का केवल एक तरीका भर ही नहीं माना जा सकता। संसदीय राजनीति में लोक सेवक के लिए परम्परागत जन सम्पर्क के स्थान पर पूंजीवादी मीडिया में विज्ञापन की आवश्यकता पैदा करना इसकी सैद्धांतिक देन है। इसके अतिरिक्त पेड न्यूज की कीमत का आकलन भी इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। पेड न्यूज अगर समाचार के रूप में विज्ञापन है तो यह इसका अत्यन्त सरलीकरण है। भूमंडलीकरण के आर्थिक कार्यक्रमों को लागू करने का दूसरा बड़ा औजार भाषा है। पेड न्यूज को मीडिया के माध्यम से मतदाताओं को धोखे में रखने की प्रक्रिया मात्र कह कर व्यक्त नहीं किया जा सकता।

देश में पत्रकारिता पर लोगों का भरोसा हमेशा कायम रहा है और इसे लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ मात्र कहने के लिए ही नहीं कहा जाता। भारत में भी पूरी दुनिया की तरह मीडिया का चरित्र शहरी और मध्यमवर्गीय ही रहा है। भारतीय समाज सदा लिखित और प्रकाशित सामग्री पर भरोसा करता आया है। मीडिया में विज्ञापन और समाचारों में अन्तर करना असहज होता जा रहा है। विज्ञापनों के माध्यम से ठगी और बेईमानी किया जाना आम बात है। हाल ही में एक टीवी चैनल पर शुगर की दवा के आविष्कार के समाचार को चलाया जाना इसका उदाहरण है। एंकर ने विज्ञापन को बाकायदा खबर के रूप में पेश किया। पिछले लोकसभा चुनावों में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने मतदाताओं से वायदे किए थे और उन्हें विज्ञापित किया था, उसे मतदाताओं के साथ धोखाधड़ी की श्रेणी में बढ़ कर लोकतंत्र के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है।

बाजारवाद का वास्तविक अर्थ है लोक-लुभावन तरीके से तमाम चीजों का बाजार में खड़ा किया जाना; जबकि मीडिया में समाचारों का पेश किया जाना और उस पर लोगों का विश्वास कायम होना, लम्बे राजनीतिक और सामाजिक विकास की प्रक्रिया की देन है। किन्तु समाचारों का ढांचा और उनकी भाषा तथा लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ के रूप में मीडिया की मान्यता और उसके बाद राष्ट्र को चलाने वाली संसद हेतु धन से चुनाव जीतना या सम्भव होने को लोकतंत्र की समाधि के कगार पर खड़े होने के ऐलान जैसा है। अगर इतिहास में झांकें तो पाएंगे कि आज तक देश में अधिकतर प्रेस ने अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से किया है। अमेरिका और यूरोप की प्रेस भी कभी भारतीय प्रेस की तरह निर्भीक और आजाद नहीं रही। किन्तु अब मीडिया आऊटलेट और पत्रकारिता का भेद धीरे-धीरे समाप्त होता जा रहा है; बाजार और मिशन एक हो रहे हैं। लोगों ने महसूस करना आरम्भ कर दिया है कि मीडिया बहुत है किन्तु पत्रकारिता नहीं। मीडिया की पहुंच और प्रभाव असीम व्यक्ति तक भले ही हो, पर उसके पास कहने को कुछ नहीं। मीडिया केवल वही कह और सुन सकता है, जो व्यापारी उसके प्रोग्राम में भर दे। सारी प्रक्रिया राजनीतिक वाणिज्य में तब्दील हो गई है, जिसका सबसे बड़ा उद्देश्य व्यक्तिगत स्वार्थ को सार्वजनिक हित के रूप में पेश करना, उस पर तथाकथित जन सम्मति जुटाना और फिर उससे भरपूर मुनाफा कमाना है। इस पूरे वाणिज्यिक मॉडल में मीडिया का रोल सबसे अहम है। अहम इसलिए कि अकेला मीडिया ही तथाकथित जन सहमति की आपूर्ति करने का दमखम रखता है और अपनी पहुंच के कारण मीडिया जनमत संग्रह करने का ढोंग कर सकता है। बाद में आजाद होने का स्वांग रचने के पश्चात् निजी स्वार्थ को सार्वजनिक हित के रंग में रंग सकता है।

पहले पत्रकार लोगों के मध्य उठते-बैठते थे, आत्मीयता से उनका हाल-चाल पूछते थे। किन्तु मीडियाकर्मी होने के बाद से वह कहीं भी घुसकर तब तक अपनी लाठी भांजता है, जब तक लोग डर कर या तो चुप नहीं हो जाते या फिर अपनी हामी नहीं भर देते। ये मीडिया लठैत अपने वेतन या पैसों के बदले निजी स्वार्थों के ठेकेदारों के लिए जन सहमति उपजाते हैं। ऐसी जन सहमति के लिए शोर जरूरी है, तभी बाजार की मनमानी हो सकती है जब उसे रोकने-टोकने वाले मूक हों। जन चेतना या जनमत को मूक करना ही अब मीडिया का मुख्य कार्य हो गया है। इसी अर्थ में राज्य और बाजार का कार्य सम्भव है। बाजार ने मीडिया के माध्यम से लोकसंवाद का अपहरण कर लिया है। बाजार के संगठित और संसाधन सम्पन्न होने से कोई उस पर सीधा आक्रमण नहीं कर सकता। फिर 'जिसकी लाठी, उसकी भैंस' वाली बात तो सर्वसिद्ध है ही। पत्रकारिता के मीडिया आऊटलेट में तब्दील होने से एक ही घटना को समाचार पर विभिन्न ढंग से पेश किया जा सकता है। विचार को समाचार का जामा पहनाया जा रहा है। वांछनीय विज्ञापन की तरह समाचार प्रकाशित किए जा रहे हैं। मीडिया और राजनीति दोनों पर ही धन का दबदबा कायम हुआ है। संसद की स्थायी समिति के अनुसार सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारतीय प्रेस परिषद्, समाचार प्रसार संघ, भारतीय निर्वाचन आयोग, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और प्रसार भारती जैसे सभी एजेंसियों, प्राधिकरणों और विभिन्न प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने प्रदत्त समाचार की समस्या को स्वीकार किया है और इसे रोकने के उपाय पर बल दिया है। किन्तु हैरानी की बात है कि मीडिया का अधिकांश वर्ग इस पर चुप्पी साधे हुआ है। मुम्बई और पेरिस के आतंकी हमलों की कवरेज से भारत और फ्रांस के मीडिया के चरित्र का विश्लेषण किया जा सकता है और पत्रकारिता के स्तर को आंका जा सकता है। भारतीय पत्रकारिता का रिश्ता देश के आम नागरिक से टूटता जा रहा है। पत्रकार के मीडियाकर्मी में परिवर्तित होने से इस रिश्ते में दरार आ गई है। वास्तव में जन-भागीदारी से ही स्वस्थ और निष्पक्ष पत्रकारिता सम्भव है। पत्रकारिता को पीतकारिता में परिवर्तित होने से रोकने के लिए एक ठोस और समग्र योजना का होना आवश्यक है। इसके तहत पत्रकारिता को मीडिया आऊटलेट होने से बचाने के लिए पत्रकारिता पर बाजार और सरकार दोनों के दबाव को कम किया जाना और इसे पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों के प्रति उत्तरदायी बनाया जाना लाजिमी है। स्वतंत्र नियामक आयोग के गठन के अतिरिक्त मीडिया के स्वामित्व, टीआरपी के दुश्चक्र, निजी समझौते और प्रदत्त समाचार जैसी समस्याओं के हल से ही पत्रकारिता को बचाया जा सकता है। पत्रकार और तकनीकी मिलकर इस दिशा में अहम भूमिका निभा सकते हैं। टेक्नोलॉजी ने पत्रकार को व्यापक लोक समूह से जोड़ दिया है। किन्तु पत्रकार को वास्तविक जनादेश या जनआक्रोश को बड़े लोक संवाद से जोड़ कर, अपनी और पत्रकारिता की विश्वसनीयता और गरिमा की रक्षा करनी होगी अन्यथा पत्रकारिता को लोग पीतकारिता कहने से गुरेज नहीं करेंगे।

सन्दर्भ: दैनिक समाचार-पत्र 'जनसत्ता' में प्रकाशित डॉ. मुकेश कुमार के 'सब कुछ हासिल कुछ', श्री अनिल चमड़िया के 'धोखे के बाजार में' तथा 'राष्ट्रवाद के अन्तर्विरोध', श्री अभिषेक भटनागर के 'मीडिया में पर्दा' एवं श्री मनोज सिंह के 'लोकप्रियता के मायने बदले' लेख।

क्षेत्रीय निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
क्षेत्रीय कार्यालय, धर्मशाला,
जिला-कांगड़ा (हि०प्र०)

अंतर्मुखी अंधेरे और बहिर्मुखी उजाले

अंधेरों का कोई रंग नहीं होता,
उजाले ही रंगों से छलते हैं।
आंखें उजालों की मोहताज हैं,
तभी तो छली जाती हैं।
जिन्हें अंधेरों में देखने
की कला आती है,
वे कभी छले नहीं जाते।
अंधेरों में समता होती है,
और उजाले विषम होते हैं।
आदमी को विषमता से नहीं,
समता से डर लगता है;
क्योंकि समता में निरपेक्षता होती है,
आदमी सापेक्षता चाहता है,
इसमें उसे अपने होने का आभास होता है।
आदमी को अहं से मोह होता है
यही उसका अस्त्र है
यही उसकी तलवार है
भौतिकता के अनंत सागर में
और निरपेक्षता उसके अहं का हरण कर लेती है
वह महामानव होने लगता है
उसे इसी बात का भय रहता है
कि कहीं ईश्वर हो जाने के चक्कर में
उसकी अपनी बनाई पहचान न खो जाए
इसीलिए शायद वह
अंधेरों से डरता है।

पोपी रैणा

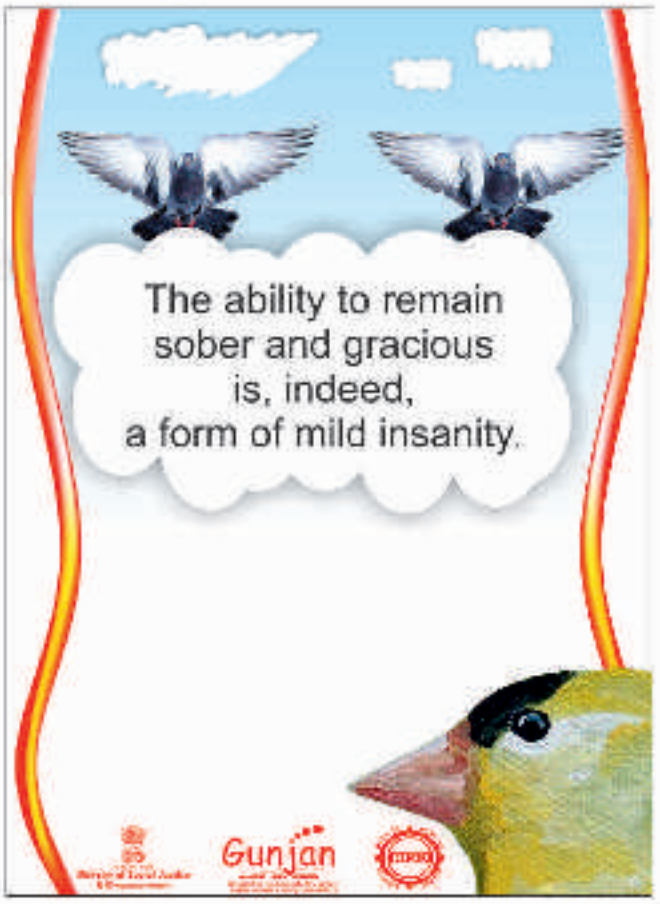

51वें जन्मदिन पर घोड़ी चढ़ेंगे सलमान

सलमान खान के प्रशंसकों के लिए ये खबर खुशी में झूमने जैसी हो सकती है। जी हां खबर आ रही है कि सलमान की शादी की तारीख तय हो गई है।

सलमान 27 दिसंबर को जहां अपना 51 वां जन्मदिन मनाएंगे उसी दिन वो अपनी शादी के लिए घोड़ी भी चढ़ेंगे। सलमान इन दिनों हर जगह अपनी रोमानिया गर्लफ्रेंड लूलिया वंतूर के साथ नजर आ रहे हैं।

हाल ही में दोनों प्रीति जिंटा की रिसेप्शन पार्टी में एक साथ पहुंचे। चर्चा थी कि सलमान यहां पर लूलिया के साथ अपनी शादी का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 'SpotBoye.com' की खबर के मुताबिक घर वालों ने सलमान और लूलिया की शादी की तारीख तय की है। हाल ही में खबरें आ रही थीं कि सलमान ने अपनी मां से शादी करने का वादा किया था।

सलमान की मां की तबीयत खराब रहती है और वो चाहती हैं कि सलमान शादी कर लें। अब ऐसा लग रहा है कि सलमान अपनी मां का सपना इस साल जरूर साकार कर देंगे।

अब 99 रुपए में स्मार्टफोन का दावा

बेंगलुरु की एक कंपनी नमोटेल ने सबसे सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च करने का दावा किया है। इसकी कीमत सिर्फ 99 रुपए बताई गई है। ग्राहकों को डिलीवरी के लिए अलग से चार्ज देने होंगे। फोन की कैश ऑन डिलीवरी होगी। कंपनी के प्रमोटर माधव रेड्डी का दावा है कि यह विश्व का सबसे सस्ता स्मार्टफोन है। हालांकि बड़ी संख्या में लोग इस दावे को संदेह की नजर से देख रहे हैं। उनका कहना है कि कंपनी की साइट यूजर्स को कहीं और ट्रांसफर कर देती है जहां निजी जानकारी मांगी जाती है, जिसका दुरुपयोग होने का खतरा है।

यह हैं खूबियां

कंपनी का दावा है कि 3जी नेटवर्क वाले इस फोन में 4 इंच का डिसप्ले है। एंड्रॉयड लॉलीपॉप 5.1 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले इस फोन में 1.3 गीगाहर्ट्ज का क्वाडकोर प्रोसेसर और 1 जीबी रैम है। दावा किया जा रहा है कि स्मार्टफोन की बुकिंग 17 से 25 मई के बीच शुरू होगी। कंपनी वेबसाइट के मुताबिक बेंगलुरु में हेडक्वार्टर वाली ये कंपनी इसी साल शुरू हुई है। स्मार्टफोन बनाने वाली इस कंपनी की पेकलाइट टेक्नोलॉजी पैरेंट कंपनी है। कंपनी की मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली और चेन्नई में ऑफिस खोलने की योजना है।

हाल में रिंगिंग बेल्स नाम की कंपनी ने फ्रीडम 251 नाम से 251 रुपए में फोन लॉन्च किया था। बाद में ये कंपनी विवादों में फंस गई और इसके खिलाफ सरकार ने जांच शुरू कर दी। स्मार्टफोन की डिलीवरी भी नहीं की गई।

बच्चों के सिर के पीछे मारना खतरनाक

कई सारे माता-पिता अपने अनुशासनहीन बच्चों के सिर के पीछे हल्के थप्पड़ को अपेक्षाकृत सुरक्षित दंड मानते हैं। लेकिन 50 साल के लंबे शोध से पता चला है कि नाराज माता-पिता को बच्चों के सिर के पीछे थप्पड़ लगाने से पहले दो बार सोचना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। शोध के अनुसार, बच्चों के सिर के पीछे हल्के थप्पड़ मारने से उनमें मानसिक समस्याओं और संज्ञानात्मक क्षमताओं का जोखिम बढ़ जाता है।

निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए शोधकर्ताओं ने पांच दशकों के डेटा का विश्लेषण किया। इस दौरान शोधार्थियों ने 1,60000 बच्चों के जीवन का आकलन किया। इस दौरान शोधार्थियों ने इस अनुभव से गुजरने वाले बच्चों और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के विकास की संभावना के बीच एक सकारात्मक संबंध पाया।

ऑस्टिन स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से इस अध्ययन की लेखिका एलिजाबेथ गेरशॉफ के अनुसार, हमने शोध में

देखा कि सिर के पीछे थप्पड़ लगाना हानिकारक निष्कर्षों के साथ संबंधित है। साथ ही माता-पिता अगर सोचते हैं कि ऐसा करने से उनके बच्चे सुधर जाएंगे, तो यह गलत है क्योंकि इस तरह का व्यवहार बच्चों को अधिक समय तक सुधार कर नहीं रख सकता है।

यहां 12 साल बाद लड़कियां बन जाती हैं लड़का

कभी-कभी हमें दुनिया के किसी कोने से बहुत ही अजीबो-गरीब किस्से देखने व सुनने को मिल जाते हैं, लेकिन डोमिनिकन रिपब्लिक में स्थित एक गांव की कहानी किसी डरावने सपने की तरह है। इस गांव में जन्मी हर लड़की युवा होते-होते लड़का बन जाती है। जी हां ये कोई कहानी नहीं बल्कि सच है-

इस गांव का नाम सेलिनास है। ये एक ऐसा गांव है यहां पहले तो लड़की पैदा होती है लेकिन जन्म के 12 साल बाद वह लड़के में परिवर्तित हो जाती है। अजीब है लेकिन ये सच है कि यहां लड़कियां टीनएज तक लड़का बन जाती हैं। दरअसल सेलिनास गांव में एक अजीब बीमारी ने बच्चों को अपनी चपेट में ले रखा है। इस बीमारी के कारण बच्चियां बड़ी होते-होते लड़का बन जाती हैं। इस बीमारी के चलते

लड़कों का लिंग न के बराबर या फिर बेहद छोटे आकार का होता है जिससे यह नहीं पता चल पाता कि बच्चा लड़का पैदा हुआ है या फिर लड़की। डॉक्टरों का कहना है कि ऐसा गर्भावस्था के दौरान आनुवंशिक विकार के कारण गर्भस्थ शिशु को जरूरी एंजाइम न मिल पाने का कारण होता है। इसकी वजह से डिहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन सेक्स हार्मोन ठीक से बन नहीं पाते हैं। इसी चलते 12 साल के बाद ही लड़के की पहचान हो पाती है।

चश्मा हटाना है तो ये खाएं

अगर आप भी लंबे समय से अपनी आंखों पर लगे चश्मे को हटाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको चिकित्सक के पास जाने की और महंगे इलाज की जरूरत नहीं है। पौष्टिक खानपान और जीवनशैली में बदलाव कर आप अपनी आंखों को स्वस्थ कर सकते हैं।

□ **गाजर** : हम लंबे समय से सुनते आ रहे हैं कि गाजर आंखों के लिए काफी अच्छा होता है, जो वास्तव में सौ प्रतिशत सच है। लेकिन अब यह समय केवल सुनने का नहीं है, बल्कि अपनाने का है। गाजर को अपने दैनिक जीवन में शामिल कर आप अपनी आंखों पर लगे मोटे चश्मे को हटा सकते हैं। इसमें पाए जाने वाले विटामिन हमारी दृष्टि के लिए बहुत लाभकारी हैं।

□ **हरी पत्तेदार सब्जियां** : ल्यूटीन और जियाक्सैथीन (रसायन) हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छे होते हैं और इनका प्रमुख स्रोत हरी पत्तेदार सब्जियां हैं। ये हमारी आंखों को शक्ति देकर दृष्टि को बेहतर करते हैं।

□ **जामुन** : जामुन में विटामिन सी की उच्च मात्रा होती है। यह आंखों की सुरक्षा करता है साथ ही मोतियाबिंद के जोखिम को घटाता है।

□ **बादाम** : विटामिन ई का उच्च स्रोत आंखों के लिए बहुत फायदेमंद है, यह आंखों के रोग मैक्युलर डिजनरेशन को कम करने के लिए असरदार है।

□ **अंडे** : अंडे की जर्दी में ल्यूटीन, जियाजैन्थीन और जिंक उच्च मात्रा में उपस्थित होता है, जो हमारी आंखों को स्वस्थ बनाने में मददगार है।

[illegible]